

प्रेषक

जी० बी० ओली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़ / चमोली / उत्तरकाशी
उत्तराखण्ड।

नियोजन अनुभाग ।

देहरादून दिनांक: २८ जनवरी, २००८

विषय: भारत सरकार द्वारा वर्ल्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये प्रथम क्रिस्त के रूप में आवंटित धनराशि की स्वीकृति।

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/18/2006 बी.ए.डी.पी.(UT*PAR) दिनांक 18.12.2006 तथा संख्या 1/18/2006 बी.ए.डी.पी.(UT*PAR) दिनांक 26.12.2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये राज्य स्तरीय स्वीनिंग कमेटी द्वारा संस्तुत रु० 1559.66 लाख की योजनाओं, जिन पर भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त है, के क्रियान्वयन के लिये जनपद मिथौरागढ़, चमोली एवं उत्तरकाशी के लिये संलग्न विवरणानुसार रु० 500.00 लाख (रुपये पाँच करोड़ मात्र) की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में आपके निर्वर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की राहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- 1- संलग्नक में उल्लिखित प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध में योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा तथा कार्य के लिये लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर उसका तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर के विभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- 2- स्वीकृत कार्यों पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज एवं मितव्ययता के विषय में समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्यों पर स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व इसके आगणन गठित कर उन पर सक्षम स्तर के अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- 3- प्रत्येक कार्य योजना का समय निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि योजना क्रियान्वयन शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित हो जाये तथा प्रस्तावित योजना चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाये।
- 4- प्रत्येक कार्य के लिये धन आवंटन की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तथा धनराशि के व्यय विवरण भी शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

- 5— समय-समय पर निर्माण कार्य में अपेक्षित गुणवत्ता बनाये रखने हेतु निरीक्षण की व्यवस्था की जायेगी और निरीक्षण की एक प्रति मण्डलायुक्त तथा शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- 6— कार्य पूर्ण कर कम्प्लीशन प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलाधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराके शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और यदि उक्त कार्य के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- 7— उक्त योजनाओं पर कार्य करने में भारतसरकार द्वारा दिशा निर्देशों का अनुपालन प्रत्येक स्थिति में सुनिश्चित किया जाय।
- 8— व्यय उन्हीं योजनाओं पर ही किया जायेगा जिनके लिये आवंटन किया जा रहा है और भद परिवर्तन का अधिकार विभाग को नहीं होगा।
- 9— स्वीकृति की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2008 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार एवं राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 10— स्वीकृति की जा रही धनराशि तत्काल सम्बन्धित विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा।
- 11— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्यय के अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्य पर पूंजीगत परियोजना-102-सामुदायिक विकास योजना-91-जिलायोजना-9101-सीमान्त विकास खण्डों का विकास-42-अन्य व्यय के नामे डाले जायेगा।
- 12— यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अ.शा. संख्या-1258/XXVII(5)/2008 दिनांक 24 जनवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

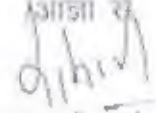
(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव।

संख्या: ५ (१) XXVI/एक-(1)/2006 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महालेखाकार(लेखाकार एवं हकदारी)उत्तराखण्ड इलाहाबाद।
- 2— आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
- 3— सचिव, लोक निर्माण विभाग।
- 4— स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5— अधर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 6— उपा सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
- 7— सम्बन्धित कक्षाधिकारी।
- 8— मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 9— मुख्य अभियन्ता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा।

- 10- अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग-पिथौरागढ़/गोपेश्वर/उत्तरकाशी।
 11- अधीक्षक अभियन्ता, निर्माण विभाग-राज्य लोक निर्माण विभाग-पिथौरागढ़/गोपेश्वर/भटवाड़ी।
 12- अध्यक्ष, बार्डर एरिया डेवलपमेंट अथारिटी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 13- वित्त अनुभाग-5/वित्त नियोजन प्रकौष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
 14- लोक निर्माण अनुभाग-2/गार्ड फाइल।
 ✓ 15- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से

 (जी० बी० ओली)
 संयुक्त सचिव।